

20



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

No. 77]

नई दिल्ली, बुधस्तिवार, मार्च 20, 2003/फाल्गुन 29, 1924

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2003/PHALGUNA 29, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2003

विषय: जापान से मेट कोक के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करना।

फा. सं. 14/41/2002-डीजीएडी.— इंडियन मेटालॉजिकल कोक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली ने घरेलू उद्योग की ओर से 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें जापान के मूल या वहां से निर्यातित 18% से कम के ऐश अंश के साथ (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) मेटालॉजिकल कोक के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जाँच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

शामिल उत्पाद

2. वर्तमान जाँच में शामिल उत्पाद 18% से कम के ऐश अंश के साथ मेटालॉजिकल कोक है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है)। विनिर्मित मेट कोक मुख्यतः कार्बन है जिसमें कुछ धातुएं तथा अवशिष्ट वाष्पशील पदार्थ हैं। मेट कोक उद्योगों में प्रयुक्त मुख्य ईंधन है जहां भट्टों में एक समान एवं उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मेट कोक (जिसमें विषयांतर्गत मेट कोक भी शामिल है) का प्रयोग पिग आयरन, ढलाईखानों, लौह मिश्रधातुओं, रसायनों तथा संपूर्ण स्टील संयंत्रों में किया जाता है। इस उत्पाद को आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण 270400 के अंतर्गत तथा

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-1 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 27.04 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग

3. यह याचिका इंडियन मेटालॉजिकल कोक मेनुफक्चरर्स एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है तथा निम्नलिखित उत्पादक याचिकाकर्ता कंपनियां हैं :-

- (i) मैसर्स बीएलए इंडस्ट्रिज लि०, मुम्बई
- (ii) मैसर्स अन्टाई बालाजी कोक लि०, कोलकाता
- (iii) मैसर्स दुर्गापुर प्रॉजेक्ट लि०, कोलकाता
- (iv) मैसर्स सौराष्ट्र फ्यूल्स प्रा० लि०, मुम्बई
- (v) मैसर्स सदरन फ्यूल्स लि०, बंगलौर
- (vi) मैसर्स सेसा कैंबला कोक कं० लि०

एक अन्य घरेलू उत्पादक मैसर्स गुजरात एनआरई ने याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता कंपनियों का संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक का हिस्सा है इसलिए याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमावली के नियम 5(3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में याचिका दायर करने के मानदंड की पूर्ति करता है।

शामिल देश

4. वर्तमान जांच में शामिल देश जापान है (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा जाएगा)।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आयातित उत्पादों तथा उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों में कोई सुस्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित विषयांतर्गत मेट कोक आयातित मेट कोक से प्रत्यक्ष विनिमेय है। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ उपरोक्त नियमावली के अर्थों में याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ता ने आस्ट्रेलिया से जापान के उत्पादकों द्वारा पोत पर्यंत निशुल्क स्तर पर की गई खरीद के कोयले की कीमतों को लेते हुए जापान में परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। कोक उत्पादन की लागत का परिकलन करने के लिए उचित आशोधनों के साथ वसूली प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय विनिर्माताओं की लागत का प्रयोग

किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर याचिकाकर्ता ने जापान में संबद्ध वस्तुओं के प्रथम दृष्टया सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

7. याचिकाकर्ता ने डीजीसीआई तथा एस के आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है। कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, जहाजी बीमा, निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभार एवं कमीशन के कारण समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

8. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से कहीं अधिक हैं जो प्रथम दृष्टया इस बात का सूचक है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन हो रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. याचिकाकर्ता ने क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर सूचना प्रस्तुत की है। मानदंड जैसे कि संबद्ध देशों से बढ़े हुए आयात, जापान से आयात की कम कीमत, अलाभकारी बिक्री कीमतों के कारण उद्योग को नुकसान, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण, लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल तथा नकद प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव समग्र एवं संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

पाटनरोधी जांच का आरंभ

10. उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2002 तक की है।

12. सूचना देना:

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में इस जाँच से जुड़े ज्ञात संबद्ध आयातकों को संबंधित सूचना निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से देने और अपने विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग

भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जाँच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है।

13. समय-सीमा

वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उनको अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूप दिए गए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना देने से मना करती है या उचित समय के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जाँच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2003

Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning import of Met Coke from Japan.

F No. 14/41/2002-DGAD.— Indian Metallurgical Coke Manufactures Association, New Delhi has filed a petition on behalf of the domestic industry in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Metallurgical Coke with an Ash content of less than 18% originating in or exported from Japan and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

PRODUCT INVOLVED

2. The product involved in the present petition is Metallurgical Coke with an Ash content of less than 18% (hereinafter referred to as subject goods). Met Coke produced is mainly carbon along with some minerals and residual volatile material. Met Coke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces. Met Coke (including subject Met Coke) is used in various industries including pig iron, foundries, ferro alloys, chemicals and integrated steel plants and others. The product is classified under Customs heading 27.04 of Schedule I of Customs Tariff Act and under ITC (HS) Classification 2704 00. This Custom classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

3. The petition has been filed by Indian Metallurgical Coke Manufactures Association, New Delhi and the following producers are the petitioner companies :

- (i) M/s BLA Industries Ltd, Mumbai
- (ii) M/s Antai Balaji Coke Ltd., Calcutta
- (iii) M/s Durgapur Project Ltd, Kolkatta
- (iv) M/s Saurashtra Fuels Pvt. Ltd, Mumbai
- (v) M/s Southern Fuels Ltd. Bangalore
- (vi) M/s Sesa Kembla Coke Co. Ltd.

Another domestic producer M/sGujarat NRE Coke Ltd. has supported the petition. The petitioner companies account for more than 50% of the total domestic production of subject goods and therefore, the petitioners satisfy the criteria of standing as domestic industry to file the petition in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

COUNTRY INVOLVED

4. The country involved in the present investigation is Japan (hereinafter referred to as the subject country).

LIKE ARTICLE

5. The petitioners have claimed that there is no noticeable difference between the imported products and the products manufactured by them. The subject Met Coke produced by the petitioner in India is directly interchangeable with imported subject Met Coke. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' to that imported from the subject country within the meaning of the Rules supra.

NORMAL VALUE

6. The petitioners have claimed Normal Value on the basis of constructed cost of production in Japan by using the Coal price at FOB level procured by Japanese producers from Australia. The cost of producing Coke has been constructed using the cost from Indian manufacturers using the recovery process with appropriate modifications. The Authority has prima facie considered the Normal value of subject goods in Japan on the basis of constructed cost of production as made available by the petitioners.

EXPORT PRICE

7. The petitioners have determined export price for subject country on the basis of the import figures of the DGCIS. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of export, port handling and port charges and commission to arrive at the Export Price at ex-factory level.

DUMPING MARGIN

8. There is sufficient evidence that Normal Value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject country.

INJURY AND CAUSAL LINK

9. Petitioners have furnished information on various parameters relating to injury. Parameters such as increased imports from subject country, low price of imports from Japan, losses to the industry due to unremunerative selling price, price under selling, price under cutting, negative returns on capital employed and negative effect on cash flows prima-facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2001 – 30th June, 2002.

SUBMISSION OF INFORMATION

12. The exporters in the subject country and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority